



Paid To Savour The Magic Of Reading

The experiment raises an amusing but important question: if people need to be paid to read, what does that say about the future of books?

Samudragupta's Horses

The Fish with Armor-Like Scales

‘ज्ञानेश कुमार कहाँ मिलेगा, मोदी जी की गोदी में’

चुनाव आयुक्त ने सांसदों से नहीं मिल पाने के कारण गिनाए

वैसे तो नारों का स्तर गिरता ही है, धरने-प्रदर्शनों में, पर, प्रियंका जी का यह नारा, अपनी गिरावट के कारण काफी समय तक याद रहेगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। राहुल और प्रियंका के लिए सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर यह दूसरा दिन था। विपक्ष के नेताओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए सरकार ने हिरासत और बंद पैमाने पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने जनपथ स्थित सागर रत्ना में विपक्ष के लिए लंच का आयोजन किया।

लंच के बाद विपक्षी सांसद जंतर-मंतर जाना चाहते थे और वहां घरना देना चाहते थे। उनका कहना था कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन के लिए वही जगह तय की है।

सांसद बसों में सवार हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर तक जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि, वहां कई बैरिकेड्स लगे थे और बड़ी संख्या में पुरुष और महिला पुलिसकर्मों तैनात थे।

जंतर-मंतर पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई थी और विपक्षी सांसदों को वहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई।

- प्रियंका जी ने जब यह नारा लगाया, वे मैरीडियन होटल के “राउन्डआउट” के पास जमीन पर लेटी थीं तथा उनके हाथ में संविधान की एक कॉपी थी तथा राहुल गांधी उनक पास मंडरा रहे थे, पुलिस को प्रियंका जी को घसीट कर बस में ले जाने से रोकने के लिए।
- इससे पूर्व कांग्रेसअध्यक्ष ने रेस्टोरेन्ट, सागर रत्ना में, विपक्ष के सांसदा का लंच रखा था, धरने-प्रदर्शन की आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए।

इसके बाद विपक्षी सांसद मेरिडियन होटल के गोलचक्कर के पास सड़क पर ही बैठ गए। पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा दिखाई दे रहा था।

बाद में राहुल और प्रियंका को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का बड़ा दल वहां पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी और शाह ने दोनों भाई-बहन को गिरफ्तार करने के लिए पूरी पुलिस मशीनरी लगा दी हो।

दोनों ने पूरी ताकत के साथ इसका विरोध किया।

प्रियंका सड़क पर लेटी हुई थीं, नारे लगा रही थीं और उनके हाथ में संविधान की एक प्रति थी। राहुल गांधी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। इंडिया गठबंधन के सांसदों के चुनाव आयोग की ओर मार्च करने और पूरे दिन विरोध प्रदर्शन करने के कुछ घंटे बाद, चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम को कहा कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से आयोग से बैठक के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने कहा कि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलना चाहता है और एक ज्ञापन सौंपना चाहता है।

आयोग ने कहा कि उसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ राजनीतिक दलों के आयोग मुख्यालय की ओर मार्च के दौरान, कुछ सांसद अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे।

आयोग ने एक बयान में कहा, ”आज शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव आयोग से बैठक के लिए समय नहीं मांगा था।”

शाम करीब 4 बजे आयोग को

दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना चाहता है और एक ज्ञापन सौंपना चाहता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- शाम को चार बजे चुनाव आयोग को सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी उनके मिलना चाहते हैं।
- चुनाव आयुक्त के अनुसार, दिल्ली पुलिस से उन्हें सूचना मिली कि 240 सांसदों का ग्रुप उनसे मिलने आ रहा है, इस पॉल्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में।
- चुनाव आयुक्त ने इस पर कहा कि स्थापित परम्परा के अनुसार, चुनाव आयुक्त के परिसर में ही मुलाकात हो सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं।
- अतः चुनाव आयुक्त ने अपना एक उच्चाधिकारी, इन सांसदों से मिलने के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया, जिसे सांसदों ने “रिजैक्ट” कर दिया।

बाँग्लादेश के प्र.मंत्री बार-बार भारत यात्रा क्यों टाल रहे हैं?

प्र.मंत्री बनने के बाद वे मलेशिया, चीन, जापान, सऊदी अरब व टर्की की राजकीय यात्रा कर चुके हैं

प्र.मंत्री बनने के बाद वे मलेशिया, चीन, जापान, सऊदी अरब व टर्की की राजकीय यात्रा कर चुके हैं

रैंपो रेट से मतलब है, वह ब्याज दर, जो आरबीआई चार्ज करती है, व्यवसायिक बैंकों से अल्पकालीन ऋणों पर

-श्रीरंज झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार की प्रक्रिया लगातार रुकी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान लंबे समय से प्रस्तावित अपनी भारत यात्रा को बार-बार टाल रहे हैं। नवंबर या दिसंबर में संभावित यात्रा की तारीख अभी भी तय नहीं हुई है।

फरवरी 2026 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में काफी गिरावट आई है।

शेख हसीना की पिछली अवामी लीग सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी मजबूत थे। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, संपर्क और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग हुआ था। जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया, उन्हें भारत भागना पड़ा।

- पर, बाँग्लादेश के प्र.मंत्री तारिक रहमान, भारत से कुछ चौंकने हैं तथा “सबसे पहले बाँग्लादेश ही रहेगा”, इस नारे के तहत, बाँग्लादेश की सार्वभौमिकता, बराबरी व गैर हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करते हुए, भारत द्वारा आयोजित “ब्रिक्स सम्मेलन” में भी नहीं आए।

और बाद में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे पूरी स्थिति ही बदल गई।

बीएनपी का रुख ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रभाव को लेकर अधिक सतर्क रहा है। पार्टी ने “बांग्लादेश फस्ट” विदेश नीति अपनाई है, जिसमें देश की संप्रभुता, समानता और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया गया है। तारिक रहमान ने मलेशिया, चीन, जापान, सऊदी अरब और तुर्किए की यात्राओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निमंत्रण के बावजूद हिस्सा नहीं लिया। इससे संकेत मिलता है कि बांग्लादेश

जानबूझ भारत-केन्द्रित नीति से अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दोनों देशों के बीच एक बड़ा मुद्दा शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर है। दाका लगातार इस मामले में प्रगति चाहता है। बांग्लादेश ने 2013 की द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत, उनकी वापसी की औपचारिक मांग की है, ताकि वे नवंबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई मौत की सजा का सामना कर सकें। यह सजा 2024 के आंदोलन के दौरान कथित मानवता-विरोधी अपराधों के लिए सुनाई गई थी।

शेख हसीना ने स्वयं भी कई बार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। आरबीआई के रैंपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट (0.25 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के फैसले से यह दर 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गई है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में कर्ज लेना थोड़ा महंगा हो जाएगा।

रैंपो रेट वह दर है, जिस पर आरबीआई कर्मशायल बैंकों को कम अवधि के लिए पैसा उधार देता है। जब आरबीआई इसे बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए पैसे की लागत बढ़ने लगती है। इसके बाद बैंक कर्ज की ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और कारोबार के लिए मिलने वाला कर्ज महंगा हो सकता है।

इसका उद्देश्य मांग को इतना कम करना है कि महंगाई लंबे समय तक बनी न रहे। ऊंची ब्याज दरें नए कर्ज और निवेश को कम कर सकती हैं, बचत को बढ़ावा दे सकती हैं और आखिरकार कीमतों पर दबाव कम कर सकती हैं। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण

- इस रैंपो रेट के बढ़ने से, बैंकों से चार्ज किए जा रहे ब्याज दर में भारी परिवर्तन होगा।
- आरबीआई का इतनी थोड़ी सी रेट बढ़ाने का मतलब है, बैंकिंग इण्डस्ट्री को मैसेज देना कि आरबीआई महंगाई (इनफ्लेशन) के बारे में संवेदनशील हैं और अगर महंगाई पर नियंत्रण हासिल नहीं हुआ तो आरबीआई कुछ “ग्रेथर” का बलिदान भी कर सकती हैं, महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए।

है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि आरबीआई महंगाई के हालात को लेकर पहले की तुलना में कम आश्वस्त है। अगर आर्थिक विकास की दर अच्छी बनी हुई है और महंगाई बढ़ रही है, तो केन्द्रीय बैंक के पास बहुत उदार मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाए रखने की वजह कम हो जाती है।

आरबीआई के लिए समस्या केवल मौजूदा महंगाई की दर नहीं है, बल्कि इस बात की आशंका भी है कि ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें, कच्चा तेल, कमीडिटी की कीमतें, मजदूरी और

लेने वालों पर सबसे ज्यादा दिखेगा, जिनके लोन फ्लोटिंग या एक्स्टर्नल बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपये का फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया है और बैंक पूरी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का बोझ ग्राहक पर डाल देता है, तो उसके ब्याज का खर्च बढ़ सकता है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है, ब्याज दर कब और कैसे बदली जाती है, लोन की कितनी अवधि बाकी है और बैंक क्या फैसला करता है।

मौजूदा फिक्स्ड रेट वाले कर्ज लेने वालों पर आमतौर पर इसका तुरंत असर नहीं पड़ेगा।

जमाकर्ताओं को इस बढ़ोतरी का फायदा हो सकता है। बैंकों के बीच जमा राशि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य ब्याज देने वाले उत्पादों पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। आरबीआई के सामने एक मुश्किल संतुलन बनाए रखने की चुनौती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी आडवाणी से मिलने उनके घर गये

मोदी आडवाणी से मिलने उनके घर गये

मोदी आडवाणी से मिलने उनके घर गये

पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत का रिकार्ड बनाएगी- पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि सांसदों को निर्वाचन आयोग से मिलाने के स्थान पर थाने ले जाया गया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 7 अक्टूबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने राजस्थान के पंचायतीराज चुनावों में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, इस बार पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत का रिकार्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तथा अच्छे और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा।

- उन्होंने कहा कि आडवाणी के दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन ने स्थायी छाप छोड़ी है।

आवास पर मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि उन्होंने आडवाणी जी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आडवाणी के दशकों लंबे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

युवाओं को भी चुनाव में मौका देने पर जोर रहेगा। पायलट ने ये बातें बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के वॉर रूम में मीडिया से रूबरू होकर कहीं।

इससे पहले पायलट ने एआईसीसी राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में आयोजित कैपेन कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पंचायतीराज चुनावों के प्रचार, प्रत्याशी चयन, संगठन को राजस्थान में सक्रिय करने समेत कई मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई।

सचिन पायलट ने कहा कि आगामी पंचायतीराज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वर्ष 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले अंतिम बड़ा चुनाव पंचायतों का है। पार्टी ने जिलों की स्थिति पर चर्चा

करी, चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तय की है।

निकाय चुनावों का उल्लेख करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा जीतकर भी हार गई और कांग्रेस हारकर भी जीती है, क्योंकि कांग्रेस का वोट ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कई जिलों से शिकायतें मिलीं

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पंचायत चुनाव लड़ेगी तथा अच्छे, साफ छवि वाले व युवाओं को टिकट दिया जाएगा।